भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@gov.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र संख्या 8बी/यू.पी./06/04/2020/एफ.सी. 1954 दिनांकः 09.10.2020

सेवा में,

प्रमूख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ, ।

Online Proposal No. FP/UP/Approach/38153/2020

विषय: यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में चित्रकूट वन प्रभाग में प्रभावित 3.2275 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 164 वृक्षों/पौधों के पातन, बांदा वन प्रभाग में प्रभावित 7.8758 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 641 वृक्षों/ पौधों का पातन, हमीरपुर वन प्रभाग में प्रभावित 8.65 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 1.6747 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा 458 वृक्षों/पौधों का पातन, महोबा वन प्रभाग में प्रभावित 2.4868 हे0 संरक्षित वनमूमि एवं 3565 वृक्षों/पौधों का पातन, जालौन वन प्रभाग में प्रभावित 11.913 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 6.411 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा 329 वृक्षों/पौधों का पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 22.9393 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 4.8059 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा 172485 वृक्षों/पौधों का पातन, इटावा वन प्रभाग में प्रभावित 7.2940 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 12655 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल योग 77.278 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 190297 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक संख्या-1980/81-2-2020-800(07)/2020 दिनांक-25-09-2020.

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विशेष सचिव उ0प्र0 सरकार द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.02.2020 द्वारा प्रस्ताव में सैध्दान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसको उल्लिखित शर्तों की अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में चित्रकूट वन प्रभाग में प्रभावित 3.2275 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 164 वृक्षों/पौधों के पातन, बांदा वन प्रभाग में प्रभावित 7.8758 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 641 वृक्षों/ पौधों का पातन, हमीरपुर वन प्रभाग में प्रभावित 8.65 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 1.6747 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा 458 वृक्षों/पौधों का पातन, महोबा वन प्रभाग में प्रभावित 2.4868 हे0 संरक्षित वनमूमि एवं 3565 वृक्षों/पौधों का पातन, जालौन वन प्रभाग में प्रभावित 11.913 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 6.411 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा 329 वृक्षों/पौधों का पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 22.9393 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 4.8059 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा 172485 वृक्षों/पौधों का पातन, इटावा वन प्रभाग में प्रभावित 7.2940 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 12655 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल योग 77.278 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 190297 वृक्षों/पौधों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 55.4161 ha. Non Forest Land in (22.9393 ha. Non forest land Compartment / Gata No. 321, 322/2 मि0, 323/2 मि0, Village- Jaitpur, Tehsil-Auraiya, District-Auraiya) (7.30ha. Non Forest land Compartment / Gata No. 1451, 1463, 281ख, 273छ, 5ग 14घ, 1560ग, Village- Sarawan Tehsil-Takha (Bharthana), District Etawah) (4.04 ha. Non forest land Compartment / Gata No. 1593/2,Village-Bandhauli, Tehsil-Orai, District Jalaun) (2.4868 ha. Non forest land, Compartment / Gata No. 480 मि0, Village-Khanna Tehsil-Mahoba, District Mahoba) (10.65 ha. Non forest land Compartment / Gata No. 299 मि0/68मि0,Village-Aurakhera, Tehsil-Raath, District Hamirpur) (08 ha. Non forest land Compartment / Gata No.

261ख Village-Achraur, Tehsil-Banda, District-Banda) and 53 ha. Degraded forest land in (Compartment/Khasra No. Not provided, Village-Bargarh, Tehsil-Chitrakoot, District-Chitrakoot) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species will be avoided.

4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5. User Agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department.
6. User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.
7. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.
8. The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.
9. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
10. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
11. No labour camp shall be established on the forest land.
12. If feasible translocation of trees proposed for felling should be explored.
13. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
14. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
15. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
16. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
17. The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the Court orders, provisions, rules, regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.
18. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
19. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
20. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग,17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), 17, राणा प्रताप मार्ग लखनऊ उ0 प्र0।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, चित्रकूट, बांदा, महोबा, इटावा, औरैया, जालौन।
4. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्रधिकरण विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रतीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली

09/10/2020
(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)